(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) भानु प्रताप सिंह समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है तथा समिति को विभिन्न सिफारिशों से संबंधित सूचना कुछ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की जानी है ।

"राष्ट्रीय कृषि नीति" के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार

1418. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
कुमारी आलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों और कृषि विश्वविद्यालयों ने "राष्ट्रीय कृषि नीति" के प्रारूप के संबंध में अपनी टिप्पणियां केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नीति को कब तक लागू किये जाने की संभावना और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे क्रियान्वित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

Fertiliser Subsidy

1419. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI RAM AWADHESH SINGH:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the value of fertilizer subsidy given during 1991-92 and that targeted for 1992-93;

(b) what has been the impact of cut in the subsidy in the cost of agricultural products like wheat and rice per acre due; and

(c) whether it is a fact that a large section of farmers has demanded withdrawal of subsidy altogether, if so, the reasons therefore.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The budget provision for fertiliser subsidy during 1991-92 is Rs. 4800 crores and for 1992-93 it is Rs. 5000 crores.

(b) A statement indicating revised cost of cultivation of wheat and paddy per acre after taking into account the 30% increase in fertiliser prices is enclosed (*See* below)

(c) No, Sir.